भारतीय जन समूहों के लिए AIIB की चुनौतियां?

द रिसर्च कलेक्टिव

भारतीय जनसमूहों के लिए AIIB कि चुनोतियाँ

जून 2018

द रिसर्च कलेक्टिव

द रिसर्च कलेक्टिव, प्रोग्राम फॉर सोशल एक्शान की भाोध इकाई है, जो विकास, उद्योग, दीर्घकालीन विकल्प, समान वृद्धि, प्राकृतिक संसाधन, समुदाय और जन अधिकार के सैद्धान्तिक ढांचों और व्यावहारिक पहलुओं पर रिसर्च को संचालित करता है। अर्थ शास्त्र, कानून, राजनीति, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान जैसे विभिन्न विशयों को समेटते हुए, उसका काम लोगों के अनुभवों और समुदाय के परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। हमारे काम का मकसद है जमीनी हक़ीकत को प्रतिबिम्बित करना, विनाशकारी विकास के प्रतिमानों को चुनौती देना तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण सम्बन्धी और सांस्कृतिक मसलों को लेकर जानकारी पर आध ाारित बहस को जन्म देना।

डिजाईन : मुस्तुजाब माक्कोलत

निजी वितरण हेतु

प्रतियों के लिए संपर्क करें:
F10/12, बेसमेंट, मालवीय नगर,
नई दिल्ली–110017

ए.आई.आई.बी. (AIIB) क्या है ?

ए.आई.आई.बी. यानि कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का गठन 2016 में चीन के द्वारा एक नये अंतर्राशट्रीय बैंक के रूप में किया गया है। यह बैंक सरकारों और निजी सेक्टर को आधारिक संरचना के लिए पैसा देता है। इसने मुख्यता एशियाई देशों पर ध्यान केन्द्रित किया है और इसके नियमों के अनुसार एशियाई सदस्यों की बैंक में न्यूनतम 75 प्रतिशत मत होना चाहिए। परन्तु बैंक के सदस्य एशियाई देशों के अलावा विशव के अन्य हिस्सों से भी हैं जैसे– योरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका – हालांकि गौरतलब है कि यू.एस. और जापान इसके सदस्य नहीं हैं। ग्लोबल साउथ की तरह, एशिया की भी आधारिक संरचना में एक अभाव है।

बहुत सी सरकारें और अंतर्राशट्रीय विकास बैंक देशों के विकास और समृद्धि के लिए आधारिक संरचना में भारी भरकम निवेश में विश्वास रखते है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने 2017 में अनुमान लगाया था कि एशिया में बुनयादी ढांचे के समाधान के लिए 2030 तक 1.7 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्शा खर्च करने की जरूरत है। ए.आई.आ. ई.बी. का लक्ष्य इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को वित्त पोशित है।

यह बैंक चीन की एक राजनैतिक और आर्थिक परियोजना भी है और इसकी स्थापना मुख्यता चीन को एक विश्व शक्ति बनाने और पहचान दिलाने के लिए की गयी थी। ताकि विश्व बैंक आई.एम.एफ. और अन्य पारम्परिक अंतर्राशट्रीय वित्तीय संस्थानों (ए.आई.आई) का यह विकल्प बन सके। हालाँकि अभी तक यह बैंक ए.डी.बी. विशव बैंक आदि से बहुत अलग साबित नहीं हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनके लिए बहुत अधिक खतरे या प्रतिद्वंदी जैसा नहीं है।

ए.आई.आई.बी. बदलती हुई दुनिया में पश्चिम से पूरब की ओर आने वाली आर्थिक व् राजनैतिक बदलाव का प्रतीक है। इस बैंक की स्थापना और उभार ग्लोबल साउथ के तथाकथित विकासशील देशों' को इसका अधिकांश शेयर धारक बना कर किया गया है, जोकि दूसरे आई.एफ.आई. के विपरीत है।

ब्रिक्स (BRICS) का बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) दक्षिण का दूसरा बैंक है। इसमे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शाामिल हैं। ए.आई.आई.बी. ने अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ाते हुए वर्तमान में 86 देशों तक पहुंचा दिया है।

जून 2018 में मुंबई में होने वाली ए.आई.आई.बी. की ए.जी.एम.:

ए.आई.आई.बी. इस वर्श 25–26 जून को मुंबई में अपनी तीसरी वार्शिक आम बैठक आयोजित कर रहा है। प्रत्येक सदस्य देश से एक प्रतिनिधि (खासतौर से वित्त मंत्री और सरकारी अधिकारी) विचार–विमर्श, योजना और ए.आई.आई.बी. के काम को स्वीकृत करने हेतु इसमें भागीदारी करेंगे।

इससे पहले ए.आई.आई.बी. भारत में अपने पार्टनर– कोफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) के साथ कई बैठकें आयोजित कर रहा है। यह बैठकें कलकता, विशाखापटनम, अहमदाबाद, बंगलौर, गुवाहाटी, पुणे और मुंबई में हो चुकी हैं। इन बैठकों के विशय थे – मास रैपिड परिवहन प्रणाली – पोर्ट और तटीय बुनियादी ढांचा, शहरी विकास – भविश्यवादी, समावेशी और डिजिटल बुनियादी ढांचा– क्षेत्रीय विकास – स्वच्छता और नवीकरणी – उर्जा, जल और स्वच्छता – संसाधन एकत्रित करने में निजी क्षेत्रों की भागीदारी और नयी पद्धति। दिल्ली और मुंबई के बड़े होटल में दो "स्टेकहोल्डर इंगेजमेंट" भी संपन्न हुई।

भारत और ए.आई.आई.बी.:

चीन के बाद भारत ए.आई.आई.बी. में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। बैंक में भारत 7.66 प्रतिशत की भागीदारी रखता है, जोकि चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। चीन 26.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ पहले नम्बर पर है। बैंक में भारत की कुल सदस्यता पूंजी 8367.3 मिलियन डॉलर की है। चीन के अलावा भारत एकमात्र दूसरा देश है जिसका एक निर्देशक बैंक को नियंत्रित करने वाले 12 सदस्यीय मंडल में से एक है।

वित्त मंत्री और साथ ही मंत्रालय के विभिन्न अधिकारीयों द्वारा ए.आई.आई.बी. की वार्शिक बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
बैंक के पांच उपाध्यक्ष में से एक भारतीय हैं। डी.जे.पांडियन, ए.आई.आई.बी. के मुख्य निवेश अधिकारी हैं और बीजिंग में स्थित हैं। वह एक पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी रहे हैं जिन्होंने उधोग और खानों, पेट्रोकेमिकल्स और उर्जा के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में काम किया था।

ए.आई.आई.बी. द्वारा भारत को दिए गए कर्ज का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

मंजूरी की तारीख	कर्जदार	राज्य	परियोजना	सेक्टर/क्षेत्र धनराशी	(मि. लियन में)	सह – निधिकर्ता
11/04 /2018	भारतीय गणतंत्र	मध्य प्रदेश	ग्रामीण कनेक्विटी/ संयकता (सड़के)	परिवहन/ सड़के	$140	विश्व बैंक
08/12/2017	भारतीय गणतंत्र	कर्नाटक	बैंगलोर मेट्रो	परिवहन /शहरी रेल	$335	यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (इआईबी)
27/09/2017	पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	तमिलनाडू	संचरण प्रणाली को मजबूत करना	उर्जा / पॉवर	$100	एडीबी
04/07/2017	भारतीय गणतंत्रं	गुजरात	ग्रामीण सड़क योजना	परिवहन/ सड़क	$329	.....
15/06/2017	भारतीय अधिसंरचना फण्ड मोरगन स्टैनले	.....	अधिसंरचना में निजी इक्विटी निवेश	मल्टी– सेक्टर	$150	.....
02/05/2017	भारतीय गणतंत्र	आंध्र प्रदेश	24/7 सभी को उर्जा	उर्जा/ पॉवर	$160	विश्व बैंक

ए.आई.आई.बी. आखिर भारत में क्या कर रहा हैः

भारत ए.आई.आई.बी. से ऋण प्राप्तकर्ताओ में सबसे आगे है। अभी तक बैंक के वित्त का लगभग 25 % भारत ने प्राप्त किया है। ए.आई.आई.बी. की 25 स्वीकृत परियो जनाओ में से 6 भारत के नाम है। स्वीकृत परियोजनाए 1.2 बिलियन डॉलर की है और इसे बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, शहरी रेल, उर्जा और निजी क्षेत्र में लगाया जाता है।

स्वकृति के लिए 6 परियोजनाए भी है, इसके साथ ही वर्तमान में कम से कम 6 विचारणीय हैं। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 3 बिलियन डॉलर की परियोजना विचारणीय है। ए.आई.आई.बी. के वेबसाइट पर अधिकारिक तौर पर जारी सूची के अनुसार आंध्र–प्रदेश शहरी जल आपूर्ति, आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क, पश्चिम बंगाल सिंचाई एवम बाढ़ नियंत्रण, आंध्र प्रदेश अमरावती सिटी, मुंबई मेट्रो परियोजना और राश्ट्रीय निवेश एवम आधारभूत संरचना निधि शामिल है। आमतौर पर प्रस्तावित परियोजनाओ में पोर्ट का विकास, ग्रामीण कनेक्टिविटी, शहरी परिवहन, राश्ट्रीय रा. जमार्ग, बिजली व्यवस्था में सुधार, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन, जल आपूर्ति और प्रबंधन शामिल है । आने वाले वर्शो और दशको में कई और परियोजनाओ के वित्त पोशित होने की संभावनाए हैं।

दक्षिण एशिया में भारत के कई पड़ोसी देशों, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा और दक्षिण–पूर्वी एशिया, पश्चिम और मध्य एशिया में भी ए.आई.आई.बी. ने कर्ज दिया है और श्रीलंका एवम नेपाल के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

यह भारतीय आन्दोलनों के लिए महत्त्वपूर्ण क्यों है?

दो वर्शो में ए.आई.आई.बी. का काम और पहुँच महत्वपूर्ण रहा है। इसने भारत में विभिन्न परियोजनाओ को बड़ी धनराशी का कर्ज दिया है और आने वाले वर्शो में भी यह भारत में अपने कर्ज और अनुबंधों को बनाये रखेगा। अतः भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में इसका एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने रहने की सम्भावनाये है और जिसे भारतीय आंदोलन को ध्यान से देखने की जरूरत है।

भारतीय आंदोलनों और समुदायों का आईएफआई द्वारा प्राप्त कर्ज के चलते निर्मित परियोजनाओ से जुडी समस्याओ का लम्बा इतिहास है। जिसमे सामुदायिक विस्थापन, आजीविका का नुकसान, दमन और मानव अधिकार उल्लंघन और बड़े पैमाने पर पर्यावरण की क्षति का नेतृत्व इस इतिहास में शमिल हैं। नर्मदा नदी पर बने सरदार

सरोवर बाँध को विश्व बैंक से पोशण मिलना, हिमाचल प्रदेश में समस्याग्रस्त हाइड्रो परियोजनाओं को एडीबी द्वारा फण्ड देना, उड़ीसा में जीएमआर परियोजना को आइ. एफसी (विश्व बैंक का एक भाग) से फंडिंग मिलना या गुजरात में टाटा मुंद्रा परियोजना को आईएफसी और एडीबी की फंडिंग मिलना, सभी विनाशकारी विकास परियोजनाओं को ज्यादातर ग्लोबल डेवलपमेंट बैंको द्वारा अक्सर बढ़ावा और फण्ड दिया गया है। इसलिए यह मानना मुश्किल है की ए.आई.आई.बी. इनसे कुछ अलग होगा।

ए.आई.आई.बी. परियोजना पहले के बैंको से अपने आप को अलग, नया और बेहतर प्रस्तुत करता है। यह लगातार इसपर जोर देता रहा है कि यह बैंक दक्षिण से दक्षिण के लिए है और निश्चित ही इसके अन्दर अलग होने की सारी सम्भावनाये हैं। लेकिन फिलहाल इसने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है जो इसकी इस बात को साबित कर सके । यह उल्लेखनीय है की दूसरे विकास बैंको की तरह ए.आई.आई.बी. अपने मिशन वक्तव में गरीबी शब्द का उल्लेख नहीं करता है । न ही गरीबी को कम करने के लिए अपने कर्ज में किसी भी तरह की मदद करने का कोई वायदा करता है। उसका लक्ष्य सिर्फ आधारिक संरचना को बेहतर करने पर ही केन्द्रित रहता है, इसका सरल और सीधा सा मतलब है कि ए.आई.आई.बी. उन परियोजनाओं पर केन्द्रित रहेगा जोकि गरीब जनता के बजाये कॉर्पोरेट और धनी नागरिकों की सेवा करता हो।

ए.आई.आई.बी. के सन्दर्भ में राश्ट्रीय स्तर पर सूचना और पारदार्शिता की भारी कमी है तथा भारत का उस पर नजरिया पूरी तरह संज्ञान में नहीं है। इसलिए भारत सरकार बैंक के अन्दर क्या नीतियाँ निर्धारित करती है, इसको खोल पाना बहुत कठिन काम है और संसद में भी इस सवाल पर लगभग न के बराबर ही कोई विचार–विमर्श है।

ए.आई.आई.बी. 'लीन, क्लीन और ग्रीन' आधारिक संरचना होने की बात करता है । ऐसे में भारतीय आन्दोलनों को बुद्धिमानी के साथ इस नए बैंक की निगरानी करनी होगी और भारत में इसके द्वारा किये जाने वाले हस्तक्षेप को सावधानीपूर्वक बारीकी से जांचना होगा।

हमारे मुद्दों पर ए.आई.आई.बी. का क्या प्रभाव पड़ सकता है ?

अभी तो शुरुआत है और ए.आई.आई.बी. अभी अपने–आप को धीरे–धीरे स्थापित कर रहा है। हालाँकि निश्चित तौर पर भारतीय आन्दोलनों और समुदायों को आईएफआ. ई के साथ दशको के अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और इस नए बैंक के प्रति सावधान और चौकन्ना रहना चाहिए। ए.आई.आई.बी. साल दर साल अपने कर्ज की रकम को बढ़ाने का इरादा रखता है और हाल फिलहाल किसी दूसरे देशों से कहीं

ज्यादा का कर्ज भारतीय परियोजनाओं को दे रहा है। बैंक पहले से ही द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड नामक एक वित्त मध्यस्थ योजना शुरू कर चूका है और अमरावती शहर के निर्माण के लिए जिस तरह से जमीन को खरीदा गया, उसके कई मुद्दों पर शिकायते और कानूनी कार्यवाहियों के बावजूद भी बैंक अमरावती परियोजना को कर्ज देने पर विचार कर रहा है।

अब तक आन्दोलनों और नागरिक समाज की ओर से क्या चिंता आ रही हैंः

जैसा की पहले ही बताया जा चुका है, ए.आई.आई.बी. कहता है कि एक संगठन के रूप में वह 'लीन, क्लीन और ग्रीन' रहेगा। वह यह भी कहता है कि वह उन्ही परिया. `जनाओं को पोशित करेगा जोकि आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ होंगे और वह अभी तक की दूसरे आईएफआई से सीख लेगा । हालाँकि जो समूह ए.आई.आई.बी. को शुरुआती दौर से मूल्यांकन कर रहे हैं उन समूहों ने कई चिन्ताओ को जाहिर किया है।

वातावरण के स्तर पर ध्यान देने से पता चलता हैं कि ए.आई.आई.बी. ने दूसरे आइ. ंएफआई के विपरीत कोयले को स्पश्ट रूप वित्त पोशित करने से इनकार नहीं किया है । एक और बात यह भी है कि बैंक ने पर्यावरण और सामाजिक ढांचे का विकास मसौदा तैयार किया था परन्तु इस पर विमर्श करना काफी समस्याग्रस्त रहा हैः समूह को ड्राफ्ट पॉलिसी पर राय देने और विमर्श करने के लिए तो पर्याप्त समय नहीं दिया जाते थे तथा स्थानीय भाशाओ में अनुवादित दस्तावेज देने के बजाये सभी दस्तावेज अंग्रेजी में ही उपलब्ध कराया जाता था और कोई भी परामर्श आमने–सामने बैठ कर नहीं होता था।

जहाँ तक ए.आई.आई.बी. का उत्तरदयातिव और प्रभाव का सवाल है, नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं । इएसएफ, सूचना देने या प्रकटीकरण नीति और शिकायत प्रक्रिया के होने से पहले ही उसने परियोजनाओं को फंडिंग करना शुरू कर दिया था। वास्तव में अब भी संचालन शुरू होने के दो साल बाद भी यह स्पश्ट नहीं हो पाया है कि ए.आई.आई.बी. की शिकायत प्रक्रिया के सम्बन्ध में क्या हुआ है, कब इसे लागू किया जायेगा और यह कैसे संभव हो सकेगा कि प्रभावित समुदाय बैंक के द्वारा पोशित परियोजना के पहलुओं के सन्दर्भ में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा।

भारत और विश्व स्तर पर आन्दोलनों ने बुनयादी मानको, सिद्धान्तों और आईएफआई प्रउधार व्यवस्था को जिम्मेदार बनाने के लिए लम्बी और कठिन लड़ाई लड़ी है और फिलहाल यह अभी स्पश्ट नहीं है कि ए.आई.आई.बी. इन मूल्यों पर कायम रहेगा या

कमजोर पड़ जायेगा । अब तक स्पश्ट अग्रिम परामर्श नहीं है। परियोजनाओ पर समझदारी की कमी और सूचना की अस्पश्टता के चलते परियोजना पर पूर्ण सहमति बनाना मुश्किल रहा है। इसके अलावा ए.आई.आई.बी. 'अभी तक' मुख्यता अपने सह–निधि (बव–निदकमते) के पर्यवारण और समाज और अन्य मानको और प्रक्रियाओं पर निर्भर रहा है या पर्यावरण और सामाजिक राश्ट्रीय प्रक्रियाओं और कानूनों का सहारा लेता रहा है। आज भारतीय सामाजिक और पर्यावरण अधिनियम को कमजोर तथा नश्ट किया जा रहा है, ऐसे में यह एक खतरनाक सूचक है।

ए.आई.आई.बी. 'फाइनेंसियल इंटरमेडयरिस' को उधार देने का इच्छुक प्रतीत होता है, जोकि मुख्य रूप से निजी क्षेत्र का लाभ–प्राप्त फण्ड है जिनका उपयोग अधिसंरचना में निवेश के लिए किया जाता है। क्योंकी वे उसी पर्यावरणिक और सामाजिक मानको से बंधे नहीं हैं, जिससे कि आईएफआई बंधा हुआ है इसलिए इस तरह के निवेशिक फण्ड से जब भी समस्याए उत्पन्न होती हैं तब उससे जूझने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और जिनको यह फण्ड मुहिया कराते हैं उन परियोजनाओं की सूचनाओं का कोई उल्लेख नहीं करते हैं।

ए.आई.आई.बी. ने पूरे एशिया में प्रभावित समुदायों के साथ वास्तव में जुड़ने का गंभीर प्रयास नहीं किया है। जब भी विचार–विमर्श होता, वे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही होंते हैं और कोई भी दस्तावेज पूरे क्षेत्र के किसी भी स्थानीय भाशा में अनुवादित नहीं होता। समुदाय और नागरिक समाज की चिन्ताओ के किसी भी मुद्दों पर न तो बैंक ने पहुच बनायीं है और न ही किसी विशेश राश्ट्रीय या क्षेत्रीय विमर्शों को संज्ञान में लिया है। यद्यपि उसने अपने वार्शिक आम बैठकों में भागीदारी करने की सहमति दी है। वार्शिक आम बैठक (AGM) से पूर्व ए.आई.आई.बी. ने पूरे भारत में 10 'लीड अप' कार्यक्रम किये है, अधिकांशतः यह बैठकें औद्योगिक समूहों के सहयोग से की गयी हैं जिसमे शौक्षिक, निजी क्षेत्र, सरकारी अधिकारी और उद्योगिक घराने और यहाँ तक कि प्रबुद्ध मंडल के लोगों ने भागीदारी की थी। हालांकि इन बैठकों में बैंक ने नागरिक समाज और प्रभावित समुदायों को मुद्दा आधारित किसी भी बैठक में आमंत्रित नहीं किया, उन्हें दिल्ली और मुंबई के बड़े होटलों में आयोजित "स्टेकहोल्डर" की बैठकों तक सीमित कर दिया गया। उदाहरण के लिए शहरी गरीबों के बीच कार्यरत गुजरात के समूहों ने अहमदाबाद में शहरी विकास पर आयोजित सेमिनार में उनको आमंत्रित नहीं किये जाने पर यह कहते हुए अपना विरोध जताया कि "शहर में रहने वाले समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति चिंता की अस्पश्ट, गैर–पारदर्शिता और उदासीनता की प्रवृत्ति" को दर्शाता है।

मछुआरों पर ए.आई.आई.बी. का संभावित प्रभावः

मछुआरों और तटीय मुद्दों पर ए.आई.आई.बी. का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पर कुछ कहना अभी जल्दी होगा। हालाँकि, ए.आई.आई.बी. ने 'एन्हान्सिंग पोर्ट एंड का. स्टल इंफ्रास्ट्रक्चर' (Enhancing Port And Coastal Infrastructure) नामक शीर्शक पर विशाखापटनम, के मैरियट होटल में एक बैठक आयोजित की जिसका सह–आयोजक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) था। इस बैठक को मयार्क्स, पीडब्लूसी, केपीएमजी और विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिती में संबोधित किया गया। इस बैठक में सागरमाला परियोजना, समुंद्री अर्थव्यवस्था तथा अधिनियम बदलाव और निजी सेक्टर की महत्वता पर विमर्श और प्रोत्साहन दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से इस बैठक के लिए न तो कोई भी मछुआरा उपस्थित था और न हीं किसी से भी परामर्श लिया गया था। तटीय विकास की सूची एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भविश्य में ए.आई.आई.बी. भारत में निवेश करने वाला है।

वन क्षार्मिक पर ए.आई.आई.बी. का प्रभावः

यह बताना मुश्किल होगा कि वन श्रमिकों, ग्रामीण और आदिवासी समुदायों पर ए.आ. ई.आई.बी. का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह दरअसल इस बात पर भी निर्भर करता है कि भविश्य में ए.आई.आई.बी. का ऋण किस तरह भारत में आगे बढ़ेगा। परन्तु आने वाले दिनों के लिए एक बात तो बिलकुल स्पश्ट है कि ए.आई.आई.बी. भारत के लिए एक बड़ा ऋणदाता होगा और इसके संरचना के विकास और व्यापक विकास माडल को प्रभावित करेगा । इसके अलावा यह सड़क और परिवहन, उर्जा, जल, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केन्द्रित करेगा। जिससे कि पूरे देश की जमीन और जंगलो पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा ए.आई.आ. ई.बी. फिलहाल आंध्र प्रदेश की अमरावती सिटी परियोजना को पोशित करने का मन बना रहा है। यह परियोजना भूमि खरीद में देरी और पर्याप्त विवाद का विशय रही है, किसानो का दावा है कि उन पर जमीन छोड़ने के लिए दबाव डाला गया । विस्थापन के बाद पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया और राज्य सरकार ने राश्ट्रीय भूमि अधिकरण, पुनर्वास व पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 को राज्य स्तर पर बदल दिया है ताकि छोटे किसानों को दी गई भारी सुरक्षा को नजरंदाज किया जा सके और अन्य प्रावधानों के बीच सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

हम क्या कर सकते है ?

- 21 से 23 जून को आपका पीपल्स कन्वेंशन ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग (People's Convention on Infrastructure Financing) के लिए मुंबई में आपका स्वागत है।
- गंभीर रूप से विकास और अधिरचना के मुद्दे पर काम करें। क्या

  मेगा–प्रोजेक्ट, जैसा बड़े निवेश और अधिरचना के लिए बड़े ऋण वास्तव में भारत की जरूरत है? क्या इस प्रकार का निवेश गरीब भारतीयों के लिए बेहतर साबित होगा? या निगमों और पूज्जीवादों के लिए? आप और आपके समुदाय को किस तरह के विकास और अधिसंरचना की जरूरत है?
- ए.आई.आई.बी. के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़े और जाने
- ए.आई.आई.बी. के बारे में अपने समुदाय/समूह को शिक्षित करें
- भविश्य के लिए ए.आई.आई.बी. ऋण को देखे और बारीकी से ध्यान दें

और जानने के लिए निम्न वेबसाइट को देखें
https://wgonifis-net और http://www-cenfa-org